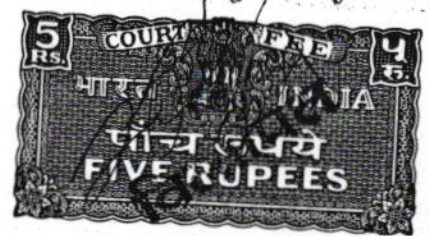


145



ef. Bist

R. 529.I/05

न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल, म० प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

12004 निगरानी

दलप्रताप दुवे पुत्र स्व० श्री जुगाराम दुवे
निवासी ग्राम खजुरी, तहसील सिंगरोली
जिला सीधी, म० प्र० -- प्रार्थी
विरुद्ध

राजेश कुमार पुत्र श्री राधेश्याम दुवे,
निवासी ग्राम खजुरी, तहसील सिंगरोली,
जिला सीधी, म० प्र० -- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश आयुक्त महोदय रीवा संभाग, रीवा
दिनांक 24-05-2008 अन्तर्गत धारा 40 म० प्र० मू राजस्व
संहिता, 1864 प्रकरण क्रमांक 263/2003-2008 निगरानी

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- (1) यहकि आयुक्त महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है।
- (2) यहकि आयुक्त महोदय ने प्रकरण के स्वरूपसक कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा।
- (3) यहकि विवादित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आदेश प्रार्थी को बिना सुने तथा बिना नोटिस के एक अशुभ न्यायालयों के अभिलेख बुलाये बिना पारित किया गया है जो न केवल कानूनन अपितु प्राकृतिक न्याया सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।
- (4) यहकि आयुक्त महोदय ने धारा 40 म० प्र० मू राजस्व संहिता के परन्तका 3 पर कोई विचार नहीं किया बिना

23/4/05
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
23 APR 2005

23/4/05

कि
देश
नरस्त

दय का
है एक
देले

दय के
।

महो

मं मूल

न है कि

महोदय

न किये

को सुन

चात

प्रार्थी

अभिना

337

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 529-एक/ 05

जिला -सीधी

क्रमांक तथा दिनांक कार्यवाही तथा आदेश पक्षी

24.8.16

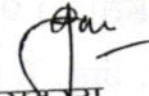
आवेदक के अधिवक्ता श्री एस० के० अवस्थी उपस्थित होकर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 226/अपील/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 25.8.04 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक दलप्रताप दुबे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित प्रकरण को आवेदक द्वारा वापिस लिया गया बाद में पुनः धारा-32 के आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को बिना आवेदक की सुनवाई के प्रचलित करने का आदेश दिया जिसके विरुद्ध अनावेदक राजेश कुमार द्वारा अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जिसे अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित ठहराते हुये निगरानी निरस्त की।



3- अभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया गया।

4- आवेदक द्वारा धारा 32 के आवेदन पर सुना नहीं गया है। अपर आयुक्त को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह अभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये प्रकरण का निराकरण करें। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।


सदस्य

✓